

2



संभागायुक्त
ने ग्रामीणों की
समस्याएं सुनी

3



68वीं ताइक्वांडो
प्रतियोगिता का
शुभारंभ

5



जाट परिवार में
जन्में सर्वोच्च पद
पर पहुंचे

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 27

प्रति सोमवार, 11 नवंबर 2024

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

बुधनी और विजयपुर का किंग कौन बनेगा और किसके हाथ लगेगी हार क्या शिवराज सिंह चौहान अपनी परंपरागत सीट पर रमाकांत भार्गव को विजयी बनाने में होंगे सफल?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में आगामी दिनों में प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होना है। वहीं, 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। यह दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस दोनों ही राजनैतिक दलों के हिसाब से स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने नंबर बढ़ाने की होड़ है। वहीं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से रमाकांत भार्गव को विजेता बनाने के लिये पुरजोर कोशिश कर रहे



क्या कांग्रेस के खाते में दो विधानसभा सीटें डालने में कामयाब होंगे जीतू पटवारी?

हैं। वहीं, कांग्रेस पार्टी भी कुछ पीछे नहीं दिखाई दे रही है। विजयपुर हो या फिर बुधनी दोनों ही विधानसभा सीटों में लगातार एक के बाद

एक सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी राजनैतिक चाल से इन सीटों में विजयी बनने के लिये कोशिश कर रहा है। राजनैतिक

सूत्रों की मानें तो मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों के उपचुनाव मोहन यादव सरकार के लिए बड़ी परीक्षा की तरह हैं। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद हो रहे इन दो सीटों के उपचुनाव की अलग-अलग चुनौतियां हैं। बुधनी में वर्ष 2003 से लगातार जीत रही भाजपा के सामने जीत का अंतर बरकरार रखने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी सीट पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे से रिक्त हो गई। वहीं, विजयपुर में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत के इस्तीफे से उपचुनाव की स्थिति बनी। अब रामनिवास रावत भाजपा प्रत्याशी हैं और उन्हें विजयी बनाना भी महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस की परंपरागत सीट



कांग्रेस ने रामनिवास रावत के विरुद्ध आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाकर चुनाव को रोचक बना दिया है। दूसरी वजह यह है कि विजयपुर कांग्रेस की ही परंपरागत सीट रही है। यहां से रामनिवास रावत ही कांग्रेस के टिकट पर छह बार विधायक रहे हैं। इसी कारण कांग्रेस के दिग्गज नेता भी यहां जोर लगा रहे हैं। सीट निकालना रामनिवास रावत के लिए इस कारण भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है क्योंकि वह विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना मंत्री बने हुए हैं। यहां भाजपा को जीत नहीं बल्कि वोटों के अंतर की चिंता है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए भाजपा संगठन और सरकार दोनों ने ही ताकत झोंक दी है।

कार्तिकेय संभाल रहे कमान



बुधनी से भले ही भाजपा ने रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है लेकिन परंपरागत सीट पर जीत का अंतर बरकरार रखने की जिम्मेदारी तो शिवराज सिंह चौहान पर ही है। शिवराज सिंह इन दिनों झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं। वे पूरा समय झारखंड को ही दे रहे हैं। बुधनी में उनके बेटे कार्तिकेय रमाकांत भार्गव के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से अपने पुराने नेता राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। राजकुमार पटेल इस सीट से 1993 में विधायक चुने गए थे। (शेष पेज 7 पर)

सेकेण्ड स्टोरी: रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव

क्या भूपेश बघेल और राजेश तिवारी के कारण हारेंगे आकाश शर्मा?

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर जनता में उत्सुकता बढ़ रही है। जहां राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने प्रचार में जुटी हैं, वहीं आम लोग भी इस चुनाव के परिणामों को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता इस चुनाव को लेकर काफी उत्सुक है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा में कोई खास टक्कर नहीं बताई जा रही है जिससे चुनावी मुकाबला रोचक नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि कांग्रेस ने यहां भी कभी जिताउ



बघेल और तिवारी के कारनामों की सजा भुगतेंगी कांग्रेस

बीजेपी के सुनील सोनी का जीतना लगभग तय

बृजमोहन अग्रवाल के कारण जीत जायेगी बीजेपी

उम्मीसदवार को टिकट ही नहीं दिया है। इस बार भी एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिसका उस क्षेत्र में कोई विशेष वजूद ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजेश तिवारी के कारण ही आकाश शर्मा को टिकट दिलवा दिया है। आकाश शर्मा राजेश तिवारी का दामाद है। जबकि राजेश तिवारी की छवि बहुत खराब है। यही कारण है कि उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है। यह इलाका बृजमोहन का गढ़ होने की वजह से उनको हरा पाना मुश्किल है। इस इलाके में बृजमोहन अग्रवाल ने बहुत सारे काम करवाए हैं। (शेष पेज 6 पर)

आय से अधिक संपत्ति के मामले में सौम्या चौरसिया को EOW ने किया गिरफ्तार

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। एक समय था जब छत्तीसगढ़ में सौम्या चौरसिया का खौफ चलता था लेकिन अब उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद सौम्या चौरसिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिनों की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कस्टोडियल रिमांड के दौरान EOW के अधिकारी सौम्या चौरसिया से आय से अधिक संपत्ति अर्जित

करने के मामले में विस्तार से पूछताछ करेंगे। सूत्रों के अनुसार, जांच के दायरे में सौम्या के कई रिश्तेदार और करीबी लोग भी आ सकते हैं, जिनके माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की गई होने की संभावना है। EOW इस दौरान उनकी संपत्तियों, बैंक खातों और लेन-देन की पूरी जांच करेगी। गौरतलब है कि 2 जुलाई 2024 को निरंबित आईएसए अधिकारी रानू साहू और समीर विश्वाकर्ष के साथ ही सौम्या चौरसिया के खिलाफ तीन नई एफआईआर दर्ज की गई थीं। इन एफआईआर में कोयला चोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप शामिल हैं। इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और अधिकारियों का मानना

है कि सौम्या के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए गए हैं, जो इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत बना सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सौम्या चौरसिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। माना जाता है कि उन्होंने अपनी ताकत और पद का दुरुपयोग कर कई गैरकानूनी सौदों में भाग लिया, जिससे उन्होंने करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की। EOW और ईडी की जांच में अब तक उनकी संपत्तियों, बैंक खातों और अघोषित संपत्तियों का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियां उनकी संपत्ति के स्रोतों का पता लगाने में जुटी हुई हैं और यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासा हो सकते हैं। (जगत फीचर्स)

कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, भाजयुमो ने लगाए मुर्दाबाद के नारे

-संवाददाता

जगत प्रवाह. पेंडा। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के द्वारा भगवा आतंक, गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी गरमा गई है। जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने पेंडा दुर्गा चौक में एकत्रित होकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव मुर्दाबाद के नारे लगाए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझपटी भी हुई। कोटा कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव

जिसे प्रार्थना सभा भवन बता रहे हैं, इस पर भाजपा नेता प्रबल प्रताप जुदेव भड़क उठे हैं, उन्होंने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पट्टे की जमीन में चर्च बनाकर आदिवासियों को धर्मांतरण करने का भी आरोप लगा चुके हैं।

जिसे लेकर हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने पेंडा दुर्गा चौक में एकत्रित होकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव मुर्दाबाद के नारे लगाए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझपटी भी हुई। (जगत फीचर्स)

संभागायुक्त तिवारी ने ग्राम चौपालों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी



-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. हरदा। नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त के. जी. तिवारी ने टिमरनी विकासखंड के ग्राम बोरपानी और गोरखाल का दौरा कर वहां ग्राम चौपाल में ग्रामीणों से चर्चा कर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में पूछताछ की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर आदित्य सिंह, जिला पंचायत की सीईओ

श्रीमती सविता झानिया, उपायुक्त जी.सी. दौहरे, एसडीएम महेश बड़ोले एवं अन्य विभागों के जिला अधिकारी भी मौजूद थे। कमिश्नर तिवारी ने ग्रामीणों से खाद बीज वितरण, उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न, नमक, शक्कर वितरण के संबंध में जानकारी भी ली। उन्होंने गांव में विद्युत आपूर्ति, स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति तथा गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उपस्थिति और टीकाकरण के संबंध में भी ग्रामीणों से पूछताछ की। स्कूल में अनुपस्थित शिक्षकों की जानकारी भी ली गई। (जगत फीचर्स)

पांचवीं और आठवीं कक्षा में होगी बोर्ड परीक्षा

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से पांचवीं और आठवीं कक्षाओं के लिए फिर से बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस नई व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा किस सत्र से लागू होगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने देशभर में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, पहली और आठवीं कक्षा के बच्चों को फेल और पास करने की नीति को समाप्त कर दिया था। 2010 से राज्य में लागू आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत

पहली और आठवीं तक के बच्चों को हमेशा पास किया जाता रहा है। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा में अनुशासन की कमी आ गई, जिससे कई बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ा। हालांकि कुछ निजी और मॉडल स्कूलों में कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग (कमजोर बच्चों को अतिरिक्त सहायता देने की प्रक्रिया) लागू की गई है, लेकिन अधिकांश सरकारी स्कूलों में यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हो पाई। इधर विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से स्कूली शिक्षा में अनुशासित शिक्षा नहीं होने से इसका विपरीत असर पड़ा है। कुछ निजी और मॉडल स्कूलों में रेमेडियल टीचिंग (कमजोर बच्चों का शिक्षण) होने

से शिक्षा व्यवस्था ठीक है। लेकिन ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान हुआ है। हालांकि परीक्षा लेने के बाद बच्चों को पास या फेल करने को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदेश में एक अप्रैल 2010 से आरटीई लागू है और तब से अब तक पहली से आठवीं तक के बच्चों को निरंतर पास ही किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता की मानिट्रिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए नई व्यवस्था लागू करने का विचार किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने आठवीं तक फेल नहीं करने की नीति में बदलाव करके फेल और पास करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। (जगत फीचर्स)

मां नर्मदा और तवा के संगम पर 13 से 15 नवंबर तक लगेगा बांद्राभान मेला, कलेक्टर-एसपी ने मेला स्थल का किया निरीक्षण

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। जिला मुख्यालय से आठ किमी दूर स्थित नर्मदा व तवा के संगम स्थल बांद्राभान में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार बांद्राभान मेला 13 से 15 नवंबर तक लगेगा। मेले की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरुकरण सिंह ने अधिकारियों के साथ मेला स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर सुश्री मीना ने निर्देश दिए कि मेला अवधि के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहें। पार्किंग, परमिट आदि की प्रक्रिया भी शीघ्र पूर्ण की जाए। मेला अवधि के दौरान होम गार्ड जवानों की टीम तथा गोताखोर भी मेला स्थल पर उपस्थित रहें। कलेक्टर ने मेला स्थल पर लगने वाली दुकानों के बिजली कनेक्शन एवं झूलों का सुरक्षा प्रमाणन



करवाए जाने के लिए भी निर्देशित किया। बांद्राभान मेला स्थल पर व्यवस्थित ले आउट डाला जाए। मेला स्थल पर बेरिकेडिंग भी अच्छे से कराए। मेला स्थल पर आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हों। उन्होंने पेयजल, चलित शौचालय आदि की भी व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रात्रि में बिजली जाने की समस्या न हो इसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। संपूर्ण मेला क्षेत्र में उचित एनाउसमेंट सिस्टम एवं कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाए। निरीक्षण के दौरान को सीईओ जिला पंचायत एसएस रावत, जिला पंचायत नर्मदापुरम के अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे एसडीएम नर्मदापुरम श्रीमती नीता कोरी, डीएसपी ट्रैफिक संतोष कुमार मिश्रा, एसडीओपी पराग सैनी, जनपद सीईओ हेमंत सूत्रकार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। (जगत फीचर्स)

एम्स भोपाल में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन

-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, 9-10 नवम्बर 2024 के बीच संस्थान के खेल समिति द्वारा कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से छात्रों और कर्मचारियों को शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्फूर्ति की ओर प्रेरित करना है। इस टूर्नामेंट में विभिन्न टीमों में भाग लेंगी और प्रत्येक टीम में सात सदस्य होंगे। प्रो सिंह ने कबड्डी और खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "कबड्डी जैसे खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानसिक ताकत और टीम भावना को भी सशक्त बनाते हैं।"

हम हमेशा से मानते हैं कि स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के बीच गहरा संबंध होता है। एम्स भोपाल में हम छात्रों और कर्मचारियों को एक स्वस्थ



जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और इस तरह के खेल आयोजनों के माध्यम से हम उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं।"

एम्स भोपाल में कबड्डी टूर्नामेंट की शुरुआत सुबह से होगी और यह पूरे दिन चलेगा। आयोजन में छात्रों और

कर्मचारियों के अलावा खेल प्रेमी भी भाग ले सकेंगे।

यह आयोजन एम्स भोपाल के छात्रों और कर्मचारियों को खेलों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और अधिक सकारात्मक बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा और साथ ही स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व को

भी उजागर करेगा। प्रो. सिंह ने इस आयोजन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, "इस टूर्नामेंट का उद्देश्य केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि खेलों के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है।"

कबड्डी जैसी खेल गतिविधियाँ छात्रों और कर्मचारियों को अपने शारीरिक

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक बेहतरीन तरीका है।" कबड्डी को भारत का पारंपरिक और अत्यंत लोकप्रिय खेल माना जाता है, जो न केवल शारीरिक ताकत और सहनशीलता को बढ़ाता है, बल्कि टीम वर्क और रणनीतिक सोच को भी प्रोत्साहित करता है। (जगत फीचर्स)

छात्र पर हुआ कटर से हमला, सीसीटी कैमरे में कैद हुई घटना



-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकला। थाना देवरी से 100 कदम की दूरी पर युवक पर किया कटर से हमला हुआ। बीए सेकंड का छात्र देवरी शासकीय नेहरू कॉलेज दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से पढ़ने जा रहा था। कालेज के गेट के सामने पहले से दो युवक बैठे थे हमले के लिए तैयार बैठे थे। नाबालिक छात्र ने बताया मैं देवरी थाना अंतर्गत बाजार वार्ड निवासी हूँ मैं नेहरू कॉलेज में द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रहा हूँ। 3 दिन पहले मेरी बहस अंश पटेल से हुए थी। आज दोपहर में अपने दोस्त सत्यम चौरसिया के साथ मोटरसाइकिल से कॉलेज जा रहा था। मोटरसाइकिल मेरा दोस्त सत्यम चौरसिया चला रहा था। जैसे ही हम लोग कॉलेज के सामने जग्गी मेडिकल के यह स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचे। उसी समय अंश पटेल और छुट्टू चोबे गली गलोच करने लगे। गाली देने से मैंने माना किया तो अंश पटेल ने मुझे बेल्ट मारा तो गाड़ी से मैं गिर गया। अंश पटेल से झोमा झटकी होने लगी तो अंश पटेल ने कट्टर निकाला और मुझे मारा जिससे मुझे पेट और पीठ में खून निकल आया। गंभीर चोट आने पर मुझे देवरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहा डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं देवरी पुलिस द्वारा कट्टर मरने वाले 02 आरोपियों पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी कर दी है। (जगत फीचर्स)

68वीं राष्ट्रीय साल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ



-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। 68 वीं राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की उद्घोषणा विदिशा के जिला खेल स्टेडियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में की गई। ताइक्वांडो प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता रघुवंशी, विशेष अतिथि के रूप में विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा तथा अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर सहित अन्य अतिथि गण शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता रघुवंशी ने कार्यक्रम में उपस्थित देश के विभिन्न अलग-अलग राज्यों से विदिशा आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल हमें अनुशासन सिखाता है इसलिए यहां आए सभी खिलाड़ी खेल को खेल भावना से खेलें, हार-जीत खेल का हिस्सा होता है। एक खिलाड़ी हारता है तो दूसरा खिलाड़ी जीतता है यदि कोई खिलाड़ी हार जाए

तो वह निराश ना हो आगे और मेहनत करें क्योंकि हार जाने के बाद भी यह अनुभव आपके जीवन में आगे काम आते हैं।

नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों से विदिशा आए खिलाड़ी हमारे देश का भविष्य हैं। उन्होंने सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खेलों को विशेष महत्व दे रहे हैं ताकि बच्चे खेल के क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे सकें। हमारा देश खेल के क्षेत्र में पीछे ना रहे और खिलाड़ी अपना और अपने भारत देश का नाम विदेश में भी रोशन करें।

प्रतियोगिता में 1473 खिलाड़ी शामिल हुए

जिला शिक्षा अधिकारी आरके ठाकुर ने बताया कि 68वीं राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जो 12 नवंबर तक जारी रहेगा। प्रतियोगिता में 14, 17 वर्ष आयुवर्ग के

बालक-बालिका खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। देश के 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 1473 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं।

राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर विदिशा के साकेत एमजीएम और वात्सल्य स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य और लोक गीत की प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गईं। साकेत एमजीएम के विद्यार्थियों के द्वारा लोकगीत की प्रस्तुति दी गई। जबकि वात्सल्य स्कूल के छात्र-छात्राओं ने योग पर केंद्रित नृत्य की प्रस्तुति दी जिसकी विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों और अतिथियों के द्वारा खूब सराहना की गई। 68वीं राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर विदिशा एसडीएम क्षितिज शर्मा, केन्द्रीय विद्यालय की प्राचार्या गीता भदौरिया, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो एम्पायर एपी राजीव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी खिलाड़ी सहित अन्य मौजूद रहे।

(जगत फीचर्स)

सम्पादकीय

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से भारत के मधुर संबंधों का कितना होगा फायदा

डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुना जाना एक महत्वपूर्ण वैश्विक घटना है। यह चुनाव न केवल वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करेगा, बल्कि कई आर्थिक बदलावों का भी कारण बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप द्वारा लिए जाने वाले नीतिगत निर्णयों के प्रभाव को समझने के लिए उनके पहले कार्यकाल पर दृष्टि डालना आवश्यक है। यह वह समय था जब ट्रंप को "टैरिफ किंग" के रूप में जाना गया। इस दौरान विशेष रूप से उभरी हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रति ट्रंप का दृष्टिकोण अधिक सख्त था। ट्रंप की आर्थिक सोच के अनुसार, कुछ विकासशील देश, विशेषकर चीन, अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए अनेक रियायतें प्राप्त करते हैं।

ये देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुल्क में छूट हासिल करते हैं। इसी कारण से ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर अधिक शुल्क (टैरिफ) लगाना शुरू किया था, जिसे आर्थिक भाषा में 'व्यापार संरक्षणवाद' कहा जाता है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन ने सोलर पैनल, वॉशिंग मशीन, स्टील, एल्यूमीनियम और चीन से आयातित कई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप, 2019 में टैरिफ से 79 बिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50% की वृद्धि थी। यह एक व्यापार युद्ध के रूप में उभर कर सामने आया, जिसमें दुनिया के दो ताकतवर राष्ट्र आपस में टकरा रहे थे।

व्यापार युद्ध वह स्थिति है जब देश एक-दूसरे के व्यापार पर अतिरिक्त कर और कोटा लगाकर आर्थिक प्रहार करते हैं। इसमें एक देश अपनी स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाता है। इसके प्रत्युत्तर में दूसरा देश भी इसी प्रकार के करों को बढ़ाकर प्रतिक्रिया देता है, जिससे "जैसे को तैसा" की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार का व्यापार युद्ध वैश्विक व्यापार में अवरोध उत्पन्न करता है, और अन्य अर्थव्यवस्थाओं को भी क्षति पहुंचता है।

अब वर्तमान पर बात करें तो, ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान वादा किया था कि वह अमेरिका की बेरोजगारी, महंगाई और अन्य आर्थिक चिंताओं को दूर करेंगे। इसके लिए वह

बहुत से नीतिगत बदलाव करेंगे, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन पर वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय हित में भी विचार किया जाना चाहिए। पहला, क्या ट्रंप एक बार फिर व्यापार युद्ध की राह पर चलेंगे? यदि वे चीन के साथ ऐसा करते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वे भारत पर भी अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाएंगे? दूसरा, ट्रंप ने घरेलू रोजगार बढ़ाने के लिए उत्पादन इकाइयों को वापस अमेरिका लाने का एलान किया है, यानी विदेश में सस्ती वस्तुएं और श्रम से उत्पादन कर रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाने का प्रयास किया जाएगा।

इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आय में वृद्धि से आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ऐसी स्थिति में क्या भारत इससे अछूता रह जाएगा? हाल के दिनों में देखा गया है कि गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां भारत को अपना नया उत्पादन केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। यदि ट्रंप के निर्णयों से व्यापार युद्धों की स्थिति आती है तो एक बार फिर आर्थिक संरक्षणवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है, और अमेरिका बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को नकार सकता है।

इसके अलावा, रोजगार के लिए अमेरिका में विदेशी श्रमिकों पर सख्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जो विशेष रूप से भारत के आईटी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध बहुत अहम हैं, क्योंकि अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और भारत का अमेरिका के साथ व्यापार में लाभ 36.74 बिलियन डॉलर (2023-24) है। ट्रंप से अच्छे रिश्ते होने के बावजूद हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कार्यकाल में भारत से स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर शुल्क लगाए गए थे और भारत को अमेरिका ने "जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी)" से बाहर कर दिया गया था, जिससे भारतीय निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। जीएसपी एक व्यापारिक योजना है जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों को शुल्क में रियायतें देते हैं, ताकि उनके उत्पादों को बाजार में बिना शुल्क या कम शुल्क पर प्रवेश मिल सके।

सियासी गहमागहमी

कैसे संभाल पायेंगे पटवारी नई कार्यकारिणी की फौज को



मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बड़ी हार मिलने के बाद कांग्रेस अंदरखाने चलने वाली खींचतान से अब तक नहीं उबर पाई है। यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के 10 माह बाद भी जीतू पटवारी अपनी टीम बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। राज्य में वर्ष 2023 में हुए

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और तत्कालीन अध्यक्ष कमलनाथ के स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी को सौंपी गई। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ही पार्टी में संभावित प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर सब की नजर थी लेकिन जब कार्यकारिणी बनी तो ऐसा लग रहा है जैसे पटवारी ने सभी को संतुष्ट करने के लिये सभी विधायकों को सूची में शामिल कर लिया हो। अब देखने वाली बात यह होगी की अनुभवविहीन इस कार्यकारिणी के सदस्यों का समन्वय पटवारी कैसे कर पाते हैं।

उपहार पाने मुख्यमंत्री के कसीदे पढ़ रहे नरोत्तम



पिछले दिनों पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रसन्न करने के लिये कांग्रेस पर निशाना साधने का प्रयास किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, "जब से मोहन भाई आप मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कांग्रेस में भगदड़ जैसे हालात हैं।" नरोत्तम मिश्रा ने यह बात तब कही

जब हाल ही में इंदौर और मुरैना से कांग्रेस के दो बड़े नेताओं का दामन छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री की चाटुकारिता में नरोत्तम इतने गिर गये कि उन्होंने कहा "कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यहां आए थे. वह सभा कर रहे थे. जीतू पटवारी इंदौर के रहने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री को मक्खन लगाने वाले मिश्रा जी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव क्या उपहार देते हैं।

हफ्ते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

झारखंड में INDIA की 7 गारंटी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं महिलाओं सहित हर निवासी को सशक्त करने वाली हैं।

भाजपा झारखंड की जनता और विशेष रूप से आदिवासियों से उनका हक छीनना चाहती है। हम किसी भी क्रिमिनल पर उसके मसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi



मध्यप्रदेश का किसान खाद संकट से जूझ रहा है और सरकार किसानों को राहत देने की बजाय इवेंट और चुनाव प्रचार में व्यस्त है।

हैरानी की बात है कि केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले में भी खाद का भीषण संकट बरकरार है।

-कमलनाथ

पदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath



राजवीरों की बात

राजस्थान के हिंदू जाट परिवार में जन्में धनखड़ सर्वोच्च पद पर पहुंचे

समता पाठक/जगत प्रवाह



उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। राज्यपाल बनने से पहले वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। 16 जुलाई, 2022 को जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। वह 1989-91 के दौरान 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान में झुंझुनू (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से संसद सदस्य थे। जगदीप धनखड़ 10वीं विधानसभा राजस्थान में 1993-1998 के दौरान किशनगढ़, राजस्थान से पूर्व विधानसभा सदस्य (एमएलए) भी हैं। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक हिंदू जाट परिवार में गोकल चंद केसरी देवी के घर हुआ था। जगदीप धनखड़ ने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ से पूरी की, और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से बी.एससी और एलएलबी में स्नातक किया। जगदीप धनखड़ ने अपनी प्राथमिक और मध्य विद्यालय की शिक्षा क्रमशः किठाना सरकारी स्कूल और घरधाना सरकारी स्कूल से पूरी की।

जगदीप धनखड़ ने 1979 में एक वकील के रूप में राजस्थान बार काउंसिल में दाखिला लिया। उन्हें 1990 में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था और शपथ लेने तक वह राज्य के सबसे वरिष्ठ नामित वरिष्ठ वकील थे। 30 जुलाई 2019 को राज्यपाल। जगदीप धनखड़ 1990 से मुख्य रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे थे। वह भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में उपस्थित हुए और राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी थे। जगदीप धनखड़ 1989-91 के दौरान 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के झुंझुनू (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से संसद सदस्य थे। धनखड़ 1993-98 के दौरान 10वीं विधानसभा चुनाव में राजस्थान के किशनगढ़ से पूर्व विधायक भी थे।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 जुलाई, 2019 को जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी. बी. राधाकृष्णन ने 30 जुलाई, 2019 को कोलकाता के राजभवन में जगदीप धनखड़ को पद की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद जगदीप धनखड़ का पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लगातार विवाद होता रहा। वह विशेष रूप से तीसरे बनर्जी मंत्रालय या पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव के बाद की हिंसा के प्रबंधन के आलोचक थे। जुलाई 2022 में, जगदीप धनखड़ को 6 अगस्त, 2022 को होने वाले 2022 के चुनाव के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था।

ग्लोबल वार्मिंग से ही कम होगा ग्लोबल वार्मिंग

जगत प्रवाह. आज “ग्लोबल वार्मिंग” एक निर्णायक मुद्दा बन गया है, जो लगातार पूरे विश्व में सुर्खियों में है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, “वैश्विक चेतावनी” (ग्लोबल वार्मिंग) शब्द पर्यावरणीय बातचीत में सामने आने लगा है। जबकि ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य ग्रीनहाउस गैसों के मानव-प्रेरित उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से है। वैश्विक चेतावनी की व्याख्या जलवायु संकट के जवाब में वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों द्वारा उठाए गए बढ़ते अलार्म के रूप में की जा सकती है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या वैश्विक चेतावनी बढ़ी हुई जागरूकता और कार्रवाई के लिए तत्काल आह्वान वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग को बदल सकती है? उत्तर जटिल है। ग्लोबल वार्मिंग के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता होगी। यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे ये वैश्विक चेतावनियाँ, वैज्ञानिक साक्ष्य, सक्रियता, नीति परिवर्तन और व्यक्तिगत कार्रवाइयों के माध्यम से, ग्लोबल वार्मिंग के प्रक्षेप पथ को बदलने की कुंजी हो सकती हैं।

वैज्ञानिक समुदाय दशकों से ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के बारे में चेतावनी देता रहा है। 1960 के दशक की शुरुआत में, वैज्ञानिकों ने मानव गतिविधि विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने और वैश्विक तापमान में वृद्धि के बीच संबंध का निरीक्षण करना शुरू कर दिया था। 20वीं सदी के अंत तक, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनेल (आईपीसीसी) का गठन हो चुका था, जो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों पर तेजी से जरूरी रिपोर्ट दे रहा था।

पृथ्वी का वायुमंडल, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), और नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) जैसी कम मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों भी शामिल हैं। ये गैसों वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं, जिससे “ग्रीनहाउस प्रभाव” पैदा होता है जो ग्रह को रहने योग्य बनाता है। हालाँकि, मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से औद्योगिकीकरण और वनों की कटाई ने इन गैसों की सांद्रता में काफी वृद्धि की है। परिणामस्वरूप, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जिससे 2020 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष के रूप में 2016 के साथ जुड़ गया है।

वैज्ञानिक समुदाय की चेतावनियाँ जोरदार और स्पष्ट हैं। यदि हम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी नहीं करते हैं, तो हमें सदी के अंत तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। इसके विनाशकारी प्रभाव होंगे। समुद्र के बढ़ते स्तर से लेकर चरम मौसम की घटनाओं, जैव विविधता की हानि और यहां तक कि मानव आबादी के

व्यापक विस्थापन तक। विज्ञान से अलावा, वैश्विक चेतावनी सड़कों से भी आ रही है। हाल के वर्षों में, जलवायु सक्रियता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। ग्रेटा थुनबर्ग के फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन से लेकर वैश्विक जलवायु हमलों तक, जिसमें लाखों लोग शामिल हैं, जनता विशेष रूप से युवा पीढ़ी तत्काल जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में मुखर हो रही है। पर्यावरणविदों का तर्क है कि सरकारें उभरते संकट से निपटने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। वे चेतावनी देते रहे हैं कि समय समाप्त होता जा रहा है, और जलवायु नीति के लिए “सामान्य रूप से व्यवसाय” दृष्टिकोण से अपूरणीय क्षति होगी। इस संदर्भ में वैश्विक चेतावनी कार्रवाई के लिए एक सामूहिक आक्रोश है, जो एक सामाजिक निर्णायक बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है जहां प्रणालीगत परिवर्तन के लिए दबाव इतना अधिक हो जाता है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

ये आंदोलन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं हैं। उन्होंने दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को राजनीतिक एजेंडे में सबसे आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई देशों में, जलवायु परिवर्तन कार्बन मूल्य निर्धारण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिबद्धताओं और सख्त पर्यावरणीय नियमों जैसे विधायी कार्यों के साथ मेल खाता है। हालाँकि, जनता के दबाव और वास्तविक नीति कार्यान्वयन के बीच अंतर महत्वपूर्ण बना हुआ है।

वैश्विक चेतावनी ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाले सबसे प्रत्यक्ष तरीकों में से एक नीतिगत परिवर्तन है। बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के जवाब में, सरकारों ने जलवायु परिवर्तन को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय पेश किए हैं। इन प्रयासों में प्रमुख था पेरिस समझौता, जिसे 2015 में 196 देशों द्वारा अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।

इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बावजूद प्रगति धीमी रही है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी), जो उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करता है, को आम तौर पर पेरिस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त माना जाता है। हाल ही में 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) ने मजबूत प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसमें कई देशों ने सदी के मध्य तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का वादा किया। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि केवल वायदे करना पर्याप्त नहीं होगा; उन्हें स्पष्ट, कार्रवाई योग्य रणनीतियों द्वारा धरातल पर लाना चाहिए। कुछ राष्ट्र दूसरों की तुलनाइस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपीय संघ 2050 तक जलवायु-तटस्थ बनने के लिए प्रतिबद्ध है और नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश कर रहा है। इसी तरह, कोस्टा रिका जैसे देश अपनी लगभग सारी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से उपयोग करके एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है, और सभी देशों- विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत जैसे प्रमुख

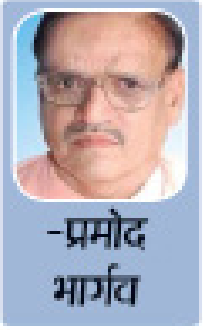
उत्सर्जकों के ठोस प्रयासों के बिना मुश्किल होंगी।

यह देखना महत्वपूर्ण है कि चेतावनियों को न केवल सुना जाए, बल्कि उन पर कार्रवाई भी की जाए। कार्बन मूल्य निर्धारण, हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना कुछ प्रमुख नितियाँ हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को धीमा कर सकते हैं। हालाँकि, इन नीतियों के कार्यान्वयन को अक्सर शक्तिशाली उद्योगों और परिवर्तन के प्रतिरोधी राजनीतिक गुटों दोनों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वैश्विक चेतावनी ग्लोबल वार्मिंग को बदलने का एक और तरीका तकनीकी नवाचार (इनोवेशन) के माध्यम से है। जैसे-जैसे सरकारें और उद्योग जलवायु वैज्ञानिकों की चेतावनियों पर ध्यान देते हैं, हरित प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ा है। सौर और पवन ऊर्जा से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों तक, ऐसी आशा है कि तकनीकी प्रगति कम कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए आवश्यक समाधान प्रदान कर सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, सौर और पवन जीवाश्म ईंधन के साथ अधिक लागत-प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर वैश्विक बदलाव भी तेज हो रहा है, प्रमुख वाहन निर्माता अगले कुछ दशकों के भीतर आंतरिक दहन इंजन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना की घोषणा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) में अनुसंधान स्टील और सीमेंट उत्पादन जैसे उद्योगों से उत्सर्जन को कम करने की क्षमता प्रदान करता है, जिन्हें डीकार्बोनाइज करना मुश्किल है।

हालाँकि ये तकनीकी प्रगति आशाजनक है, फिर भी ये चुनौतियों से रहित नहीं हैं। फिर भी, आसन्न जलवायु आपदा की वैश्विक चेतावनी से प्रेरित नवाचार, ग्लोबल वार्मिंग के प्रक्षेप पथ को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है। सरकारों और उद्योगों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे इन तकनीकों का समर्थन और विस्तार जारी रखें और यह सुनिश्चित करें कि इन्हें दुनिया भर में समान रूप से तैनात किया जाए। जबकि सरकारी नीतियाँ और तकनीकी प्रगति ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में महत्वपूर्ण हैं, व्यक्तिगत कार्रवाइयाँ भी भूमिका निभाती हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती जागरूकता या वैश्विक चेतावनी के कारण उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव आया है। अधिक लोग टिकाऊ उत्पादों को चुन रहे हैं, मांस की खपत कम कर रहे हैं और कचरे में कटौती कर रहे हैं। घरों में इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर पैनलों का उदय इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति बड़े समाधान में कैसे योगदान दे सकते हैं। वैयक्तिक कार्य, हालाँकि वैश्विक संकट के सामने छोटे प्रतीत होते हैं, उनका संचयी प्रभाव हो सकता है। यदि लाखों लोग कम गाड़ी चलाकर, कम उपभोग करके और कम बर्बादी करके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं, तो संयुक्त प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा, व्यक्तिगत पसंद बाजार के रुझान को प्रभावित कर सकती है, जिससे कंपनियों को अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

(जगत फीचर्स)

भारत-अमेरिका संबंधों को मिल सकते हैं नए आयाम



- प्रमोद भार्गव

दुनिया के सबसे सफल माने जाने वाले लोकतंत्र अमेरिका के चार साल बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक भारतीय मूल की उम्मीदवार कमला हैरिस को पराजित किया है। अमेरिका एक वैश्विक

आर्थिक शक्ति है, इसलिए यहां के चुनाव पर दुनिया नजरें टिकाए रखती है। क्योंकि जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है और वह अपनी पार्टी के मुताबिक नीतियों को अमल में लाता है तो विश्व प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। स्वाभाविक है भारत भी इस प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा बनता है। भारत इस समय न केवल आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि रक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता देश भी है। अतएव अमेरिका का शुभचिंतक होना भारत के लिए विदेश नीति से जुड़े मुद्दों के नजरिये से महत्वपूर्ण है। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं, इसी कारण ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों को नए आयाम मिले थे। इनमें आतंकवाद और घुसपैठ के विरुद्ध मिला समर्थन तो रहा ही है, चीन और पाकिस्तान पर भी ट्रंप नकेल कसते रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह चुनाव ऐसे समय में जीता है, जब दुनिया में दो बड़े युद्ध सालों से चल रहे हैं। बावजूद अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका द्वारा अनुशासित वैश्विक संस्थाएं इन युद्धों को रोकने में कोई भूमिका रेखांकित नहीं कर पाई। यदि ये युद्ध नहीं रोके गए तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर भी बढ़ सकती है?

आधुनिक दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की बांगडोर एक बार फिर से ट्रंप के हाथ

में है। उन्होंने इस जीत के साथ अमेरिका में इतिहास बनाया है। 131 साल बाद वे पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 2020 में चुनाव हारने के चार साल बाद सत्ता प्रमुख के रूप में पुनः वापसी की है। उनके पहले 1893 में ग्रेवर क्लीवलैंड ऐसे पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने का अवसर मिला था। ट्रंप की जीत आसान नहीं मानी जा रही थी। लेकिन उन्होंने दक्षिणपंथी नीतियों को अमल में लाने के भाषण देकर अमेरिकी मतदाताओं को धुंकीकर करने में सफलता हासिल कर ली। इसीलिए ट्रंप की जीत को अमेरिका में व्याप्त असंतोष की उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं, कि ट्रंप की इस जीत से अमेरिका में नस्लीयता बढ़ेगी और 'अमेरिका प्रथम' का दृष्टिकोण लेकर यदि ट्रंप आगे बढ़ते हैं तो समाज के वर्तमान मुद्दों के संदर्भ में धुंकीकरण बढ़ सकता है। क्योंकि ट्रंप को मिली जीत भी राजनीतिक धुंकीकरण का परिणाम है। ट्रंप ने जीत के साथ ही कह दिया है कि मैक्सिको की सीमा पर दीवार उठाई जाएगी और एक करोड़ घुपैठियों को बाहर किया जाएगा। अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप इस दिशा में काम कर चुके हैं। ट्रंप की यह नीति भारत की उस नीति का समर्थन है, जिसके तहत वह बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध घुसपैठियों को बाहर करने की निर्णायक कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और अत्याचार पर भी कड़ा रख जता चुके हैं।

ट्रंप के पिछले कार्यकाल की उदार नीतियों का ही परिणाम था कि भारत आई-2 और यू-2 अर्थात् चार देश भारत, इजरायल, अरब-अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है, इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच कहा जाता है। यह मध्यपूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत व्यापार, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय, ऊर्जा सहयोग और अन्य महत्वपूर्ण साझा हितों पर आपसी तालमेल बनाए जाता है। जिससे इस समूहों के देशों का हित सुरक्षित हो। चार देशों

का यह समूह आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसी समूह के अंतर्गत नई, दिल्ली और वाशिंगटन यूरोप में समुद्री मार्ग से आवाजाही के लिए एक जहाज गलियारा भी बनाने में लगे हैं। यह भारत से आरंभ होकर पश्चिम एशिया से गुजरता हुआ अमेरिका तक पहुंचेगा। चीन हिंद महासागर में समुद्री गलियारों को लेकर निरंतर हस्तक्षेप करता रहा है, ऐसे में यह गलियारा बन जाता है तो चीन की समुद्री जल मार्गों में दखल कम होगा। चीन के प्रति ट्रंप का रुख पहले भी सख्त रहा है। इसीलिए लगता है, ट्रंप इस गलियारों को अस्तित्व में लाने की दृष्टि से निर्णायक पहल करेंगे। अतएव इस नजरिए से ट्रंप की जीत भारत के लिए हितकारी उपलब्धि है।

ऐसा भी माना जा रहा है कि ट्रंप उन देशों पर शुल्क और आयात प्रतिबंध लगाएंगे। जिनके बारे में उन्हें आशंका है कि ये देश अमेरिकी हितों के शुभ चिंतक नहीं हैं। इनमें चीन और कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं। यदि ये उपाय संभव हुए तो भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए नए बाजार खुल सकते हैं। बार्कलेज पीएलसी ने ट्रंप की जीत के बाद एक शोध रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि व्यापार नीति के लिहाज से ट्रंप एशिया के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बार्कलेज का अनुमान है कि ट्रंप के शुल्क प्रस्ताव चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2 प्रतिशत की कमी लाएंगे और क्षेत्र की बांकी अधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डालेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, इंडोनेशिया और फिलिपींस सहित ऐसी अर्थव्यवस्थाएं उच्च शुल्क के प्रति कम संवेदनशील होंगी, जो घरेलू बाजार पर अधिक निर्भर हैं। ऐसा भी अंदाजा है कि ट्रंप भारत के मित्र होने के कारण भारत में स्थित अमेरिकी कंपनियों में बड़ा निवेश करने के रास्ते खोलेंगे। इसलिए कुल मिलाकर ट्रंप की जीत को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सकारात्मक घटना मानी जा रही है। भारत अमेरिका को वाहन, कपड़ा और दवाएं उच्च सीमा शुल्क चुकाकर निर्यात कर रहा है।

अमेरिका भारत का इस समय सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका से भारत का सालाना कारोबार 200 अरब डालर के करीब है। याद रहे चीन के बड़ा वैश्विक व्यापारी बनने में अमेरिका का ही योगदान रहा है। लेकिन ट्रंप ने संरक्षणवादी व्यापार को सुरक्षित रखने के उपाय किए तो भारत के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ट्रंप ने अमेरिका में स्नातक कर रहे भारतीय छात्रों को ग्रीन कार्ड देने का वादा किया है। इस आधार पर पांच लाख भारतीय छात्रों को अमेरिका में प्रवेश नौकरी या अन्य काम करने का अधिकार मिल सकता है। ट्रंप अमेरिका में छिपे बैठे खालिस्तानी आतंकी पत्र और अन्य अपराधियों पर भी लगाम लगा सकते हैं।

ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य और आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। बाइडेन के कार्यकाल में ये शिथिल रहे। यदि ट्रंप उन्हें सक्रिय करते हैं तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आतंकवाद की मुश्किलें की दृष्टि से ट्रंप इन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू कर सकते हैं। वैसे भी ट्रंप पाकिस्तान की बेहिचक सार्वजनिक रूप से आलोचना करते रहते हैं। 2020 में जब चीन और भारत के बीच लद्दाख के गलबान क्षेत्र में सैन्य झड़पे हुई थीं, तब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से दोनों देशों के बीच समझौते के लिए मध्यस्थता करने की बात कही थी। लेकिन भारत की बड़ी चिंता ईरान को लेकर हो सकती है। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। इसमें अरबों रुबए खर्च होंगे। लेकिन ये बंदरगाह बन जाता है तो भारत को ईरान से तेल आयात करने में सुविधा रहेगी। ट्रंप ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंधों पर भी फैसेला ले सकते हैं। हालांकि इस समय भारत एक बड़ी आर्थिक और भूराजनीतिक शक्ति है और उसकी इस शक्ति का लोहा मुस्लिम देशों समेत पूरी दुनिया मान रही है। इन्हीं ताकतों का परिणाम है कि चीन का रुख बदला है और दोनों देशों सीमा से सैनिक पीछे हटा रहे हैं। इस भारतीय शक्ति का ही परिणाम है कि भारत-चीन सीमा पर शांति बहाल हो रही है।

यया भूपेश बघेल और राजेश तिवारी के कारण हारेंगे आकाश शर्मा?

(पेज 1 का शेष)

उनके काम को जनता देख रही है। बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा को पसंद करते हैं और इस बार दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में यहां से बीजेपी की जीत होगी। दक्षिण विधानसभा बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है। यहां के वे पूर्व विधायक हैं। उनकी काट का आज तक कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं आया है। इस बार बीजेपी से सुनील सोनी जरूर चुनावी मैदान में हैं लेकिन क्षेत्र की जनता बृजमोहन अग्रवाल के कहने पर वोट करती है। इसका लाभ सुनील सोनी को मिलेगा। बृजमोहन अग्रवाल यहां से आठ बार चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए उनके नाम का यहां माहौल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में वहां से कांग्रेस ने एक कमजोर प्रत्याशी को खड़ा करके सीट बीजेपी को सौंपी है। रायपुर दक्षिण में कुल 19 वार्ड हैं। जिनमें से 11 वार्ड पर कांग्रेस का कब्जा है।

बीजेपी जहां स्थानीय नेता के भरोसे ही चुनाव जीतने की योजना पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। माना जा रहा है कि तीन दशक के बाद इस सीट से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला है तो इस बार जनता इस सीट पर बीजेपी को बदलेगी। इसी उम्मीद को लेकर के कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी एक तरह से निश्चित होकर राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक लोग इस बात को मन में बिठा लिया है कि ये सीट बीजेपी के ही खाते में आएगी। यही वजह है कि दिल्ली का कोई नेता अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं आया है। बात कांग्रेस की करें तो

छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी को इस बात का भरोसा है कि रायपुर दक्षिण बृजमोहन अग्रवाल के भरोसे ही वो जीत जाएगी। सुनील सोनी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर निष्क्रियता का भी आरोप लगा है। सुनील सोनी सांसद रहे, महापौर रहे, वो सब बृजमोहन की कृपा से। उन्होंने कभी किसी के काम नहीं किये। अगर जीते तो बृजमोहन के समर्थन के कारण जीतेंगे।

कांग्रेस ने कमी भी जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया

रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से कन्हैया लाल अग्रवाल ने एक बार चुनाव लड़ा था, जो सक्षम थे जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से बृजमोहन अग्रवाल को कड़ी टक्कर दी थी। कन्हैयालाल अग्रवाल मात्र 17000 वोटों से हारे थे। ये बृजमोहन अग्रवाल की सबसे छोटी जीत थी। उसके बाद भूपेश बघेल ने कन्हैयालाल अग्रवाल को टिकट नहीं दिया। महेन्द्र सुंदरदास को टिकट दिया था। रायपुर दक्षिण की अब तक की सबसे बड़ी हार सुंदरदास की हुई थी। इस बार भी कांग्रेस से प्रमोद दुबे टिकट के दावेदार थे। वो जीतने वाले उम्मीदवार थे लेकिन भूपेश बघेल और राजेश तिवारी ने फिर से कांग्रेस पार्टी को हरवाने के लिये राजेश तिवारी के दामाद आकाश शर्मा को टिकट दे दिया। अब आकाश शर्मा का हारना अब लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि आकाश शर्मा का रायपुर दक्षिण के लोगों से पूर्व में कोई भी संपर्क नहीं रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी इस बात की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है कि रायपुर दक्षिण की सीट कांग्रेसियों ने हराने के लिये तय कर रखी है। कांग्रेस का प्रत्याशी इसलिए भी नहीं जीतता क्योंकि समय के रहते टिकट नहीं दिया। इस बार तो प्रत्याशी ही कमजोर

देखा गया। वैसे तो आकाश शर्मा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। परंतु इतने से काम नहीं चलता। अगर आकाश शर्मा राजेश तिवारी के दामाद नहीं होते तो भी जीत की संभावना हो सकती थी। राजेश तिवारी के चुनाव प्रभाव कार्यप्रणाली से लोगों में घनी नाराजगी है।

कौन हैं राजेश तिवारी?

राजेश तिवारी कांकेर जिला पंचायत उपाध्यक्ष थे। उस समय रवि श्रीवास्तव कांकेर नगर पालिका के अध्यक्ष थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। रवि श्रीवास्तव लोगों के चहेते थे। लोग चाहते थे कि कांकेर नगर पालिका अध्यक्ष के लिये रवि श्रीवास्तव की पत्नी को टिकट मिले। राजेश तिवारी ने रवि श्रीवास्तव की पत्नी का नाम कटवाकर अपनी पत्नी को टिकट दिलवाई। राजेश तिवारी ने कांग्रेस में अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। हालांकि रवि श्रीवास्तव की पत्नी आरती श्रीवास्तव निर्दलीय चुनाव लड़ी और प्रचण्ड बहुमत से जीत गईं। बस्तर के आदिवासी राजेश तिवारी को नापसंद करते थे। सन 2000 में महेन्द्र कर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिये उनके साथ हो गये। अजीत जोगी, नंदकुमार पटेल, चरणदास महंत के समय में राजेश तिवारी को कोई महत्व नहीं मिला। भूपेश बघेल के समय राजेश तिवारी मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गये। वन अधिकार पट्टे देने के मामले में राजेश तिवारी की खूब चली। और इन्होंने काफी भ्रष्टाचार और घपला किया। इसके कारण एकता परिषद जैसे कई जन संगठन नाराज हो गये। इन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ विपरीत वातावरण बनाया और हरवाने में मदद की। राजेश तिवारी कांकेर में आदिवासी के नाम से पेट्रोल पंप चला रहे थे, अपराध दर्ज हुआ था। अजीत जोगी के समय में इनको जेल भेजा गया था। वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा राजेश तिवारी के दामाद हैं।

कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक: रायपुर दक्षिण विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। स्टार प्रचारक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, चरणदास महंत, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित राज्य के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि रायपुर दक्षिण इस बार बदलाव करेगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है।

कांग्रेस के लिए चुनौती है चुनाव: रायपुर दक्षिण के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। 1985 में रायपुर में 02 विधानसभा सीटें होती थी। दोनों पर कांग्रेस का कब्जा था। 1990 के विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और रायपुर टाउन की सीट जीतकर बीजेपी के खाते में डाली थी। 1985 के चुनाव में कांग्रेस रायपुर विधानसभा की सीट जीती थी। उसके बाद रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल जिस सीट से लड़ रहे हैं। उस सीट पर कभी भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। अब 2024 में बृजमोहन अग्रवाल रायपुर में विधानसभा की किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि रायपुर दक्षिण एक बार फिर उनके पास आ सकती है।

आकाश शर्मा के हो रहे वीडियो वायरल: अभी हाल ही में कांग्रेस प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह भाजपाईयों को चोर, गुंडा जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद लोगों का कहना है कि आकाश शर्मा भी अपने ससुर राजेश तिवारी की भाषा बोलने लगे हैं जबकि अभी वह विधायक भी नहीं बने हैं। इस तरह की भाषा का उपयोग करके वह अपने आपको गुंडे जैसी छवि के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं।

चिकित्सा को मूल अधिकार का दर्जा मिले



-रघु ठाकुर

पिछले लगभग 4-5 वर्षों से सारी दुनिया नये नये प्रकार की महामारियों से पीड़ित है और इससे भारत में ही लाखों मौत के शिकार हुये हैं। अनेकों अंतरराष्ट्रीय अध्ययनकर्ताओं ने इनसे मृतकों की संख्या 30-40 लाख भी बताई है, वैसे भी भारत में अनेकों बीमारियों के

चलते लाखों लोग मौत के शिकार होते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों का नाम पहले यदाकदा सुनने को मिलता था, अब लाखों लोग कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर के अस्पताल भरे पड़े हैं और हजारों लोग प्रतिवर्ष मौत के शिकार हो रहे हैं। जिनमें अधिकांश लोग वे हैं जिन्हें ईलाज उपलब्ध नहीं है या एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है, जिन्हें ईलाज पर्याप्त नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार टी.बी. जैसी बीमारियां भी हजारों लोगों की जान ले लेती हैं, प्रदूषण तो इतनी गंभीर समस्या बन गई है कि महानगरों के छोटे-छोटे बच्चे भी अस्थमा, श्वास जनित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सरकार तक प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त करती रही है। परंतु मर्ज लाईलाज है। मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में आयुष्मान योजना की घोषणा की थी। गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को 5 लाख रुपये तक का ईलाज सरकार की ओर से देने की घोषणा की थी। वैसे यह योजना अच्छी थी परंतु इस योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ। एक तो राज्य सरकारों ने अपनी सुविधा और अनुकूलता से आयुष्मान योजना के लिये अस्पताल चिन्हित किये।

अधिकांश मामलों में आयुष्मान कार्ड की 5 लाख रुपये की राशि का भारी भ्रष्टाचार हुआ। कई निजी अस्पतालों में तो चिकित्सक और मरीजों के बीच समझौता जैसा हो गया और मामूली सी बीमारी को बड़ी से बड़ी बीमारी बताकर पैसे का बंटवारा कर लिया गया। पिछले दिनों एक रपट छपी थी कि भारत सरकार ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर जो जांच कराई उनमें कई हजार करोड़ रुपयों का घोटाला का भ्रष्टाचार पाया गया।

अभी तक हमारे देश में जो चिकित्सा की व्यवस्था है वह निम्न हिस्सों में बंटी हुई है।

1. केंद्र सरकार के कर्मचारी सीजीएसएच योजना के पात्र होते हैं और उन्हें सेवा कार्यकाल में और सेवानिवृत्ति के बाद भी मुफ्त ईलाज मिलता है। इसी प्रकार सेना, सीआरपीएफ, आरपीएफ आदि केंद्र कार्य या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त ईलाज की व्यवस्था है।

2. राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सेवाकाल में ईलाज मुफ्त मिलता है और सेवानिवृत्ति के बाद भी कई प्रकार की योजनाएं उनकी चिकित्सा के लिये बनाई गई हैं।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये यदा बैंक, एविएशन, स्टील प्लांट, कोयला क्षेत्र, लोह क्षेत्र, बंदरगाह

आदि के कर्मचारियों के लिये उनकी नियोजित संस्थाओं की ओर से ईलाज की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे संस्थानों ने खुद अस्पताल बनाये हैं जिनमें बेहतर ईलाज की व्यवस्था है। और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने वालों ने बड़ी-बड़ी नामधारी निजी अस्पतालों के साथ समझौता किया है जहां उन्हें समुचित ईलाज की व्यवस्था है।

4. बहुत सारे सरकारी, गैर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को संस्थानों की ओर से सामूहिक चिकित्सा बीमा की योजना लागू की गई है।

5. गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को भी सरकारी चिकित्सालयों में या प्रशासन की मदद से मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

6. देश के अमीरों और उच्च, मध्यम वर्ग के ईलाज के लिये उनके पास देश व विदेश में पर्याप्त साधन हैं। देश का व्यापारी तबका कारपोरेट कारखानेदार इसमें आते हैं यानि ये सब मिलाकर लगभग 20-25 करोड़ लोग होते हैं जिन्हें चाहे सरकार से चाहे संस्थान या चाहे बीमा से या अपनी क्षमता से निशुल्क ईलाज की व्यवस्था उपलब्ध है। और अगर यह मान लिया जाये कि इनके परिवार में औसतन 4-5 लोग हैं तो औसतन 90 से 100 करोड़ लोगों को सरकारी या गैर सरकारी चिकित्सा उपलब्ध है। देश के राजनेताओं, सांसदों या पूर्व सांसदों, विधायकों को क्रमशः लोकसभा या विधानसभाओं के माध्यम से श्रेष्ठतम निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध है। इस आधार पर लगता है कि देश के मध्यम वर्ग के लोग, कुछ मध्यम किसान, पत्रकार ही वे अभागे लोग हैं जिन्हें निशुल्क सरकारी चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। जिनकी आर्थिक क्षमता भी ईलाज लायक नहीं है। और जो गरीब हैं, न अमीर हैं, न कर्मचारी हैं, न व्यापारी हैं बल्कि ऐसे भारतीय हैं जिनके पास आर्थिक या राजनैतिक ताकत नहीं है। इसलिये वे व्यवस्था से पूर्णतः उपेक्षित हैं। इन्हें मामूली से बुखार जैसी बीमारी की चिंता होती है कि ईलाज कैसे होगा? क्योंकि सरकारी अस्पताल या तो बहुत दूर हैं और हैं भी तो उनमें इतनी भीड़ है कि ईलाज पाना दुष्कर कार्य है। निजी अस्पतालों में उन्हें ईलाज पाना कठिन होता है। मामूली बुखार के ईलाज में फीस, दवा व जांच में कई हजार खर्च हो जाते हैं।

वैसे तो देश में एम्स, सिम्स जैसे बड़े-बड़े सरकारी अस्पताल स्थापित किये गये हैं परंतु वहां आने वाले मरीजों की संख्या और चिकित्सकों की उपलब्धता अकल्पनीय है। हमारे एक साथी श्याम सुंदर यादव की बेटी को, अपने बेटे का एक छोटा सा आपरेशन कराना है जो दिल्ली के एम्स में होना है। उसके पहले वह आगरा के निजी चिकित्सालय में अपनी क्षमता भर ईलाज करा चुकी परंतु उससे उन्हें लाभ नहीं हुआ।

अब उनसे कहा गया है कि एक छोटा सा आपरेशन दिल्ली एम्स में होगा। वह दिल्ली बेटे को लेकर गये थे और दिल्ली के डॉक्टर ने उसे देखा, आपरेशन के लिये कहा और आपरेशन के लिये ढाई वर्ष बाद की तारीख दी है। मैं इसमें एम्स संस्थान या उसके कुशल चिकित्सकों का कोई दोष नहीं मानता, क्योंकि वे लोग अपनी पूरी क्षमता से, लगन व मेहनत से ईलाज करते हैं परंतु मरीजों

की संख्या इतनी ज्यादा है कि वे स्वतः भी लाचार हैं। यह खाका इसलिये खींचा है ताकि सरकार समझ सके कि सरकार चिकित्सा और ईलाज के लिये जो तरीका अपना रही है उससे देश की बड़ी आबादी को चिकित्सा मिलना संभव नहीं है। फिर सरकारी अस्पतालों में ईलाज और दवाओं के नाम पर भी भेदभाव होता है। अफसरशाही राजनेताओं या उनकी सिफारिश वालों के लिये न केवल बेहतर ईलाज मिल जाता है बल्कि ब्रांडेड दवाइयां भी मिल जाती है। मरीज ज्यादा हैं और सरकार का दवाओं के लिये बजट जरूरत से काफी कम रहता है। इसका परिणाम यह है। अस्पतालों में दो प्रकार की दवाओं की खरीद होती है, एक सामान्य मरीजों के लिये जेनेरिक और लोकल मेड जैसी दवाओं की खरीदी होती है जो बीमारी को मिटाने लिये सक्षम नहीं होती, लंबे समय तक मरीज यह दवायें, गोण्डियां खाते रहते हैं और बाद किसी दिन कोई नर्स या कम्पाउंडर सलाह दे देता है कि यहाँ की दवाओं से फायदा नहीं होगा, बाहर से ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां खरीदो जो भारी महंगी होती हैं। जबकि राजनेताओं, अफसर और ताकतवर लोगों को ब्रांडेड दवायें उपलब्ध रहती हैं। सरकार को चाहिये कि वह इसका भी अध्ययन कराये कि सरकारी चिकित्सालयों ने कितनी दवाइयां जिनेरिक खरीदी गयीं और कितनी ब्रांडेड। तथा ब्रांडेड दवाइयां किनको दी तथा जिनेरिक दवाइयां किनको दी गई।

अधिकांश सरकारी अस्पताल के सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके लिये सरकारी अस्पताल केवल मरीजों को रिफर करने का संस्थान है, जहां से वे मरीजों को अपने निजी अस्पतालों में रिफर कर देते हैं। हालात इतने बदतर हैं कि कितने ही डॉक्टर जिन्हें मरीज अपना भगवान मानता है, उनसे वे साहूकार जैसा व्यवहार करते हैं, यद्यपि सभी नहीं कुछ अपवाद भी है। प्राइवेट डॉक्टर तो आमतौर पर मरीज की आर्थिक स्थिति देखते हैं और फिर फीस आदि का निर्धारण करते हैं। कितने ही जांच करने वाले संस्थान, दवा बेचने वालों को मैं जानता हूँ जो डॉ. साहेबान को जांच और दवा लिखने के बदले में एक निश्चित कमीशन की राशि देते हैं। देशी-विदेशी बड़ी-बड़ी दवा निर्माता कंपनियां चिकित्सक साहबानो को विदेशों की यात्रा कराते हैं, पुरस्कार देते हैं और यह सब क्यों होता है, यह सब कौन नहीं जानता?

निजी चिकित्सालय और बड़े-बड़े नाम वाले चिकित्सालय, गैर चिकित्सक पूंजीपति लोग हैं। अस्पताल तो ठहरने के लिये पाँच सितारा होटलों जैसी बन गयी, जिनका भारी भरकम किराया होता है और जांच के नाम पर विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, जिन्हें कुछ राशि दी जाती है और बकाया अस्पताल के मालिक के पास जाता है। अति संपन्न मरीजों को इनमें ईलाज कराना फायदेमंद ही है क्योंकि टैक्स बचता है। भारतीय संविधान के अनुसार चिकित्सा यद्यपि अभी तक मूल अधिकार नहीं है परंतु संविधान के डायरेक्टेड प्रिंसिपल में है। डायरेक्टेड प्रिंसिपल नीति निर्देश संविधान बनाते समय उन विषयों के लिये समाहित करने के लिय तय किये गये थे जिन्हें आज से 75 साल पहले और आजादी के तत्काल बाद क्रियान्वित करने की सरकार के पास संसाधन की क्षमता नहीं थी और

इसलिये इस उम्मीद के साथ कि कुछ ही समय में सरकारें इन्हें संविधानिक अधिकार बनायेगी, नीति निर्देश के रूप में रखा गया था परंतु सरकार ने अभी तक चिकित्सा को संवैधानिक मूल अधिकार नहीं बनाया। हालांकि मैं यह जानता हूँ कि अकेले मूल अधिकार के खण्ड में शामिल करने मात्र से सबको चिकित्सा तत्काल उपलब्ध नहीं होगी। शिक्षा के लिये मूल अधिकार में शामिल किया गया परंतु वह बहुत सफल नहीं हुआ व सरकारों ने कुछ प्रतिशत सीटें गरीब छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षित करने का नियम बनाया, परंतु उन निजी शिक्षण संस्थानों को वे बाध्य नहीं कर सके। एक तो इसलिये भी कि निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों के हाथ बड़े लंबे हैं और आमतौर पर वे जिस श्रेणी और संपन्न वर्ग से आते हैं वह सत्ताधीशों का अपना वर्ग होता है, जिस पर हाथ डालना या दबाव बनाना सरकारों के लिए आसान नहीं होता, और कुल मिलाकर ढाक के तीन पात रह जाते हैं। जब तक सरकार संपूर्ण शिक्षा का सरकारीकरण नहीं करेगी तब तक शिक्षा का मूल अधिकार संविधान के पत्रों में दर्ज रहेगा परंतु जमीन पर नहीं उतरेगा।

इसलिये भारत सरकार से मैं व लो.स.पा. पिछले दो दशकों से लगातार विभिन्न माध्यमों से मांग कर रही है कि चिकित्सा को मूल अधिकार के खण्ड में शामिल किया जाये, चिकित्सा का संपूर्ण सरकारीकरण किया जाये और चिकित्सा सबको मिल सके यह व्यवस्था की जाये। जैसा मैंने ऊपर बताया कि 90-100 करोड़ लोगों के पास निजी या सरकारी पर्याप्त चिकित्सा के साधन है। भारत के 40-50 करोड़ लोग ही इससे वंचित हैं। इसलिये अगर सरकार चिकित्सा को मूल अधिकार और सबको आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने का प्रावधान करेगी तो ही हल निकलेगा, और इसके लिये चिकित्सा का संपूर्ण रूप से सरकारीकरण जरूरी होगा। अगर सरकार यह करेगी तो जहाँ एक तरफ सभी को जरूरत के अनुसार चिकित्सा मिलेगी, बेहतर दवाइयां मिलेगी, भ्रष्टाचार व लूट बंद होगी साथ ही कोई विशेष राशि भी नहीं लगेगी। दुनिया के कई देशों में यहां तक कि ब्यूबा जैसे छोटे-छोटे देशों में यह व्यवस्था बनाई गई है व सफल है। जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति थीं तो हमारी पार्टी के धरने व ज्ञापन के बाद उन्होंने अपने स्तर पर एक पहल शुरू की थी। मैं उनका आभारी हूँ। और यह प्रस्ताव काफी दूर तक गया था। परंतु उनके राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वह प्रस्ताव टंडे बस्ते में चला गया। आज देश की राष्ट्रपति महिला है और अपनी सभी संवैधानिक लाचारियों के बाद भी वह संवेदनशील हैं। वे आदिवासी हैं और आदिवासी की पीड़ा को, उनके हालातों को, बीमारी से उनकी मौतों को उनसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं उनसे अपील करूँगा कि पद पर व्यक्ति कोई भी हो परन्तु भारत के राष्ट्रपति की संस्था की ओर से जो पहल की गई थी उस पहल को वे पुनरु क्रियाशील बनायें। प्रधानमंत्री जी को सलाह दें और चिकित्सा को मूल अधिकार में शामिल कराने तथा सबको जरूरी चिकित्सा उपलब्ध कराने तथा चिकित्सा को संपूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र में लाने की पहल करें। इस निर्णय से देश के करोड़ों लोगों को जीवनदान मिलेगा।

बुदनी और विजयपुर का किंग कौन बनेगा और किसके हाथ लगेगा हार

(पेज 1 का शेष)

उनके जातिगत वोट भी यहां बड़ी संख्या में है इसलिए भाजपा के सामने जीत का पिछला रिकार्ड बरकरार रखने की चुनौती है। वहीं श्योपुर की विजयपुर सीट पर वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत की प्रतिष्ठा बचाने के लिए संगठन और सरकार जुट गए हैं।

मोहन यादव ने बना रखी है बराबर नजर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधनी में सैकड़ों करोड़ रुपयों के कार्यों के शुभारंभ के साथ और नौ अक्टूबर को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में वन समितियों का सम्मेलन कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। दोनों सीटों पर उनका विशेष ध्यान है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा

ने भी दोनों सीटों पर कार्यकर्ताओं की बैठक से लेकर बूथ प्रबंधन तक जमावट कर ली है।

बुदनी में 20 उम्मीदवार

बुदनी विधानसभा उप चुनाव में नामांकन वापसी के बाद उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। 23 में से 3 उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है, अब 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से भाजपा के रमाकांत भागव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच सीधी टक्कर है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 76 हजार 799 मतदाता, जिसमें 1,33,280 महिलाएं और 1,43,111 पुरुष हैं। वहीं 06 थर्ड जेंडर और 194 सर्विस वोटर्स हैं। बुधनी में 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

बुधनी में तीन प्रत्याशियों में खींचतान

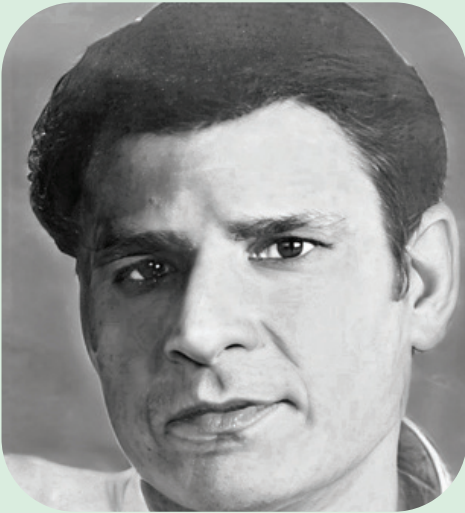
जयप्रकाश जनता दल के उम्मीदवार पंकज मौर्य,

राइट टू रिकाल पार्टी के अभिषेक चौधरी और निर्दलीय उम्मीदवार अजय सिंह ने फार्म वापस लिया है। अब रमाकांत भागव भाजपा, राजकुमार पटेल कांग्रेस, प्रदीप कुमार निर्दलीय, गजराज सिंह निर्दलीय, भीम सिंह निर्दलीय, दिलीप सिंह आजाद समाज पार्टी कांशीराम, दुर्गा प्रसाद सेन निर्दलीय, साधना भारत आदिवासी पार्टी, राजकुमार गौर निर्दलीय, विवेक दुबे निर्दलीय, सुधीर कुमार, निर्दलीय, सुजीप निर्दलीय, रामपाल भुसरीया निर्दलीय, आरती शर्मा आम आदमी पार्टी, आनंद कुमार श्याम निर्दलीय, अर्जुन समाजवादी पार्टी, राम प्रसाद पटेल निर्दलीय, रामप्रसाद पटेल क्रांति जनशक्ति पार्टी, अब्दुल राशिद निर्दलीय, धर्मेंद्र सिंह पंवार राइट टू रिकाल पार्टी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बुधनी में भाजपा प्रत्याशी पूर्व सांसद रमाकांत भागव और कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल के बीच है। जबकि समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को मैदान में खड़ा किया है।

विजयपुर में 11 प्रत्याशी मैदान में

विजयपुर में 11 प्रत्याशी मैदान में है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के विरोध में निर्दलीय नामांकन भरने वाले बैजनाथ कुशवाहा भी मैदान में कूद पड़े थे, हालांकि पार्टी ने उन्हें मना लिया। यहां सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला है। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला भाजपा के मंत्री रामनिवास रावत से हो रहा है। रावत कुछ समय पहले ही कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। और वे इसी सीट से विधायक भी थे। उनके इस्तीफे के कारण ही यह उपचुनाव हो रहा है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 54 हजार 817 वोटर हैं, जिनमें 1,21,001 महिलाएं और 1,33,554 पुरुष हैं। दो थर्ड जेंडर और 103 सर्विस वोटर्स हैं।

कलम के सिपाही...

शांत, सरल और सहज
व्यक्तित्व के गजलकार
रहे हैं दुष्यंत कुमारआज की
बात
प्रवीण
कवकड़
स्वतंत्र लेखक

अत्यंत लोकप्रिय हिंदी गजलकार दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तरप्रदेश के बिजनौर जनपद के राजपुर नवादा में 01 सितम्बर, 1933 को हुआ था। उनका मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था और उन्होंने अपने काव्य-लेखन का आरंभ दुष्यंत कुमार परदेशी के नाम से किया था। कविताएँ दसवीं कक्षा से ही लिखने लगे थे जिसे आगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दिनों नया आयाम मिला। इन दिनों वह 'परिमल' और 'नए पत्ते' जैसी संस्थाओं के साथ सक्रिय रहे और उन्हें इलाहाबाद में सक्रिय साहित्यकारों का सान्निध्य मिला। उन दिनों इलाहाबाद में कमलेश्वर, मार्कण्डेय और दुष्यंत की मित्रता लोकप्रिय रही थी। वह कविता, नाटक, एकांकी, उपन्यास सदृश विधाओं में एक समान लेखन करते रहे थे लेकिन उन्हें कालजयी लोकप्रियता गजलों से प्राप्त हुई। 'हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं' जैसी पंक्तियों के साथ समय की विडंबनाओं को प्रश्नगत करती उनकी अभिव्यक्ति संसद से सड़क तक गूँजती है और आम आदमी उनमें अपनी आवाज की तलाश कर पाता है। लोगों की जुबाँ पर चढ़ी उनकी गजलों समय की परख करने और उससे लड़ने का हथियार बन सामने आती हैं।

'सूर्य का स्वागत', 'आवाजों के घेरे', 'जलते हुए वन का वसंत' उनके काव्य-संग्रह हैं जबकि 'छोटे-छोटे सवाल', 'आँगन में एक वृक्ष' और 'दुहरी जिंदगी' के रूप में उन्होंने उपन्यास विधा में योगदान किया है। 'और मसीहा मर गया' उनका प्रसिद्ध नाटक है और 'मन के कोण' उनके द्वारा रचित एकांकी है। उन्होंने 'एक कंठ विषपायी' शीर्षक काव्य-नाटक की भी रचना की है। उनके स्थायी यश का आधार उनका इकलौता गजल-संग्रह 'साथे में धूप' है जिसकी दर्जनाधिक गजलें हिंदी-देश के संवाद और संबोधन में रोज़मर्रा का साथ निभाती हैं। 30 दिसम्बर 1975 को महज 42 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है। 'दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय' में उनकी धरोहरों को सँभालने का प्रयास किया गया है।

सेवानिवृत्ति: अनुभवी पारी का आगाज़, नई ऊर्जा और नये लक्ष्य के साथ करें नई शुरुआत

आज की
बात
प्रवीण
कवकड़
स्वतंत्र लेखक

शासकीय सेवाकाल में सेवानिवृत्ति की तारीख की गणना सेवा शुरुआत करने के दिन से ही शुरू हो जाती है। सारे लक्ष्य, सारे उसूल और सारे मापदंड को हम एक तारीख के साथ जोड़ देते हैं, जो कई बार नकारात्मक विचारों के साथ इसे सेवा का नहीं बल्कि खुशियों का अंत दिखने लगता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल परे है। सेवा निवृत्ति दर असल आपके दीर्घकालिक अनुभवों और हसरतों के साथ नये अध्याय की जोरदार शुरुआत का शंखनाद होती है। मैंने पिछले दो दिनों में ऐसी दो महान विभूतियों को खोया है, जिनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सेवानिवृत्ति के बाद ही शुरू हुआ। पहले डॉ. एमएल भाटी जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र राणापुर में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और पीड़ितों की सेवा और मानवता की सर्वश्रेष्ठ मिसाल बनकर लोगों के दिलों में राज करते रहे। दूसरे रिटायर्ड डीएसपी एनएस जादौन जिन्होंने सैकड़ों बुजुर्गों की सेवा की, उन्हें कानूनी अधिकार दिलाए और समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान किया। वे रिटायरमेंट के बात से अपने जीवन की अंतिम सांस तक बुजुर्गों की सेवा में लगे रहे। इन दोनों विभूतियों के कार्यों ने जहाँ मुझे गौरवान्वित किया, वहीं इनके अनंत यात्रा पर जाने ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं सोचने पर विवश हो गया कि कैसे इन विभूतियों ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेकंड इनिंग समाज सेवा में खेली और ऐसी खेली कि

उसे हमेशा याद रखा जाएगा। यह बात हमें यह संदेश देती है कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए कर सकते हैं। आज हमें अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम अपने अनुभव और ज्ञान से समाज में एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं।

मैं सभी सेवानिवृत्त लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने जीवन की सेकंड इनिंग को समाज सेवा के लिए समर्पित करें। हमारे सभी के पास देने के लिए कुछ न कुछ होता है। चाहे वह समय हो, पैसा हो या फिर हमारा ज्ञान और अनुभव। आइए मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें।

डॉ. भाटी के बारे में मैं बात करूँ तो दशकों पहले जब आदिवासी क्षेत्र राणापुर में कोई संसाधन नहीं थे बिजली नहीं थी तब उन्होंने उस आदिवासी क्षेत्र में न केवल अपनी चिकित्सा की सेवाएँ दी बल्कि अपनी मानवता को निभाते हुए उन लोगों की सेवा में जीवन अर्पित कर दिया। आज जब नए डॉक्टर पढ़कर निकलते हैं तो वह आदिवासी क्षेत्रों में जाने में आनाकानी करते हैं। उन्हें डॉक्टर भाटी जैसे लोगों से सीख लेना चाहिए और मानवता की सेवा कर अपने पेशे को गौरवान्वित करना चाहिए। दूसरी और जादौन जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने पेंशनर्स एसोसिएशन, अमराई चौपाल और कई संगठनों से जुड़कर राष्ट्रीय स्तर तक कई बेहतर कार्य किये और अगर मैं उन्हें बुजुर्गों का मसीहा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने पुलिस और प्रशासन दोनों ही क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दी हैं ऐसे में मैं मेरे साथी जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वह अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर समाज सेवा के

कार्यों में जुटे और लोगों की सहायता करें पीड़ित मानवता को स्नेह प्रदान करें। हम सेवानिवृत्ति के बाद समाज को कई तरीके से सेवा प्रदान कर सकते हैं। जिसके कुछ उदाहरण निम्न हैं।

* युवाओं को मार्गदर्शन: अपने अनुभवों के आधार पर युवाओं को करियर मार्गदर्शन दे सकते हैं। विशेषकर उन युवाओं को जो पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं।

* सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम: स्कूलों और कॉलेजों में जाकर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।

* यातायात नियमों के बारे में जागरूकता: सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

* अपराध रोकथाम कार्यक्रम: मोहल्लों में जाकर अपराध रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं।

* समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करना: विभिन्न समुदायों के बीच संवाद स्थापित करके शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

* स्वयंसेवी संगठनों में शामिल होना: विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों में शामिल होकर उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

* बुजुर्गों की देखभाल: अपने क्षेत्र के बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं और उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं।

* आपदा प्रबंधन में योगदान: आपदा के समय लोगों की मदद कर सकते हैं और राहत कार्य में भाग ले सकते हैं।

हम सभी डॉक्टर भाटी और जादौन जी के आदर्शों को अपना कर अपने सेवानिवृत्ति के बाद समाजसेवा की पारी को नई शुरुआत कर सकते हैं। हम इन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं।

रेल्वे स्टेशन गाडरवारा के साथ सौतेला व्यवहार, विगत 12 वर्ष से गाडरवारा स्टेशन पर एक भी स्टॉपेज नहीं

-बद्री प्रसाद कौरव

जगत प्रवाह, गाडरवारा।

जबलपुर इटारसी के बीच सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला स्टेशन में विगत 12 वर्ष पूर्व गरीब रथ का स्टॉपेज कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। उसके बावजूद भाजपा के मोदी राज में आज तक गाडरवारा में एक भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं हुआ। गाडरवारा की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो एनटीपीसी, कोल माईस, शुगर मिले, इसके अलावा गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र

में एक नगर पालिका, तीन नगर पंचायत तथा तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 50 परसेंट लोग एवं उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 50 परसेंट लोग गाडरवारा रेलवे स्टेशन से ही रेल मार्ग का उपयोग करते हैं। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी गाडरवारा के विकास को क्यों रोका जा रहा है यह जन चर्चा का विषय बना हुआ है। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से लगी हुई मुंबई रेल मार्ग पर खंडवा लोकसभा की चर्चा करें, तो इटारसी से पहली स्टेशन खिरकिया जो हरदा जिले में जिसकी आबादी

22000 मात्र है जिसमें 15 वार्ड है जो मात्र नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त है वहां पर एक साथ 5 ट्रेनों के स्टॉपेज हो रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे।

ऐसा ही इटारसी से लगा नागपुर रोड पर 68 किलोमीटर दूर बैतूल लोकसभा क्षेत्र की पहली स्टेशन घोड़ा डोंगरी जिसकी आबादी मात्र 15000 की है जिसमें 15 वार्ड है जो नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त है वहां पर भी संघमित्रा विगत 10 साल से रुक रही है। इससे साफ प्रतीत होता है कि गाडरवारा के

विकास को जानबूझकर रोका जा रहा है। यही नहीं 2017 में जबलपुर गाडरवारा-इंदौर-रेल मार्ग स्वीकृत हुआ है। परंतु उसकी भी गाडरवारा से जानबूझकर रोका जा रहा है। कहते हैं जहां एनटीपीसी होता है वहां का चहुँ विकास होता है जिसका उदाहरण सिंगरौली देखा जा सकता है, परंतु पूरे देश में यह एक मात्र गाडरवारा है यहां एनटीपीसी होने के बावजूद भी विगत 12 वर्ष में एक भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं हुआ और मिली हुई सौगातों को रोका जा रहा है। (जगत फीचर्स)